Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

भारत निर्माण के दस वर्ष

Research Team

Abhay Singh
Research Associate
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Research Associate

Manujam Pandey
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Design

Ajit Kumar Singh
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

विषय सूची

1	भूमिका	**3**
2	भारत निर्माण – 10 साल में हुआ बुनियादी ढांचागत विकास	**5**
3	ट्रांस्पोर्टेशन में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर... PM मोदी की नेतृत्व में हो रहा काया-पलट, बदल दी तस्वीर **- विनीत कुमार**	**12**
4	एक्सप्रेसवे से लेकर वंदे भारत की सौगात, दस वर्षों में नर भारत की तस्वीर **- नवीन कुमार पाण्डेय**	**14**

भूमिका

किसी देश की आर्थिक प्रगति को आकार देने में उसकी बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की एक अहम भूमिका होती है. हमारे देश के एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण मूलभूत तत्व है. इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुनियादी ढांचे को अपने विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर व केंद्र में रखा है.

पिछली कांग्रेस की सरकार में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ता था लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी सोच और बिना किसी देरी के काम को पूरा करना देश में बुनियादी ढांचे के विकास की पहचान रही है.

प्रधानमंत्री जी ने प्रगति प्लेटफोर्म के जरिए परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी की है जिसके कारण बुनियादी ढाँचे की विभिन्न विलंबित व नई घोषित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है.

अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत अब तक के उच्चतम स्तर तक पहुँच गया है और 2014 के पूर्व के स्तरों की तुलना में लगातार अधिक बना हुआ है. ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हुई तेज वृद्धि ने दूरदराज के इलाकों में सड़क तक पहुँच को लगभग सर्वसुलभ बना दिया है.

भारतीय रेल ने भी पिछले 10 वर्षों के दौरान रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण के जरिए बड़े पैमाने पर अपनी क्षमता का विस्तार किया है. भारत की पहली स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वन्दे भारत एक्सप्रेस मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी कहती है.

यदि हवाई क्षेत्रों की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए महत्वपूर्ण क़दमों से इसे सस्ता और सुलभ बना दिया है. पिछले दस वर्षों में 84 एअरपोर्ट का निर्माण, इसके अलावा 58 हवाई अड्डे, 8 हेलीपोर्ट, 2 वाटर एयरोड्रोम, साथ ही साथ मेट्रो रेल की परियोजनाओं को 20 शहरों तक लेकर जाना सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है.

बुनियादी ढांचे के विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का दृष्टिकोण भारत के आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों पर लेकर जाने में मदद करेगा. यह नागरिकों के जीवनयापन को आसान बनाएगा, रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी करेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी स्थापित करेगा.

यह ई-बुकलेट प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हो रहे भारत के बुनियादी ढांचे के विकास का एक दस्तावेज है.

डॉ अनिर्बान गांगुली

चेयरमैन – SPMRF

भारत निर्माण – 10 साल में
हुआ बुनियादी ढांचागत विकास

देश में बुनियादी ढांचागत के परिदृश्य में क्रांति लाने को लेकर भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी यात्रा की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी का विस्तार करने के साथ ही आम लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने, शहरी सुविधाओं को विकसित करने और डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान देने के साथ सरकार ने कई परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने राजमार्गों, रेलवे एवं हवाई अड्डों के विकास से लेकर जलमार्ग और रोपवे सिस्टम को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य पूरे देश में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की शुरुआत करना है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का निर्माण शामिल है। इसके अलावा भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करके रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं, लद्दाख में हर मौसम में कनेक्टिविटी के लिए एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग जैसी परिवर्तनकारी परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, मुंबई में अटल सेतु की स्थापत्य उत्कृष्टता, ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील पुल, जायसवाल पुल और पूर्वोत्तर में ढोला-सादिया पुल से, नए भारत में बुनियादी ढांचे का परिदृश्य अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है।

सड़कों के मामले में भारत में क्रांतिकारी बदलाव

सड़क मार्गों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए देश के परिवहन बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए। इनमें आधुनिकीकरण, विस्तार और कनेक्टिविटी शामिल हैं। रणनीतिक रूप से योजना बनाकर और पर्याप्त निवेश के माध्यम से भारत अपने सड़क नेटवर्क को मजबूत और प्रभावशाली सिस्टम में बदल रहा है।

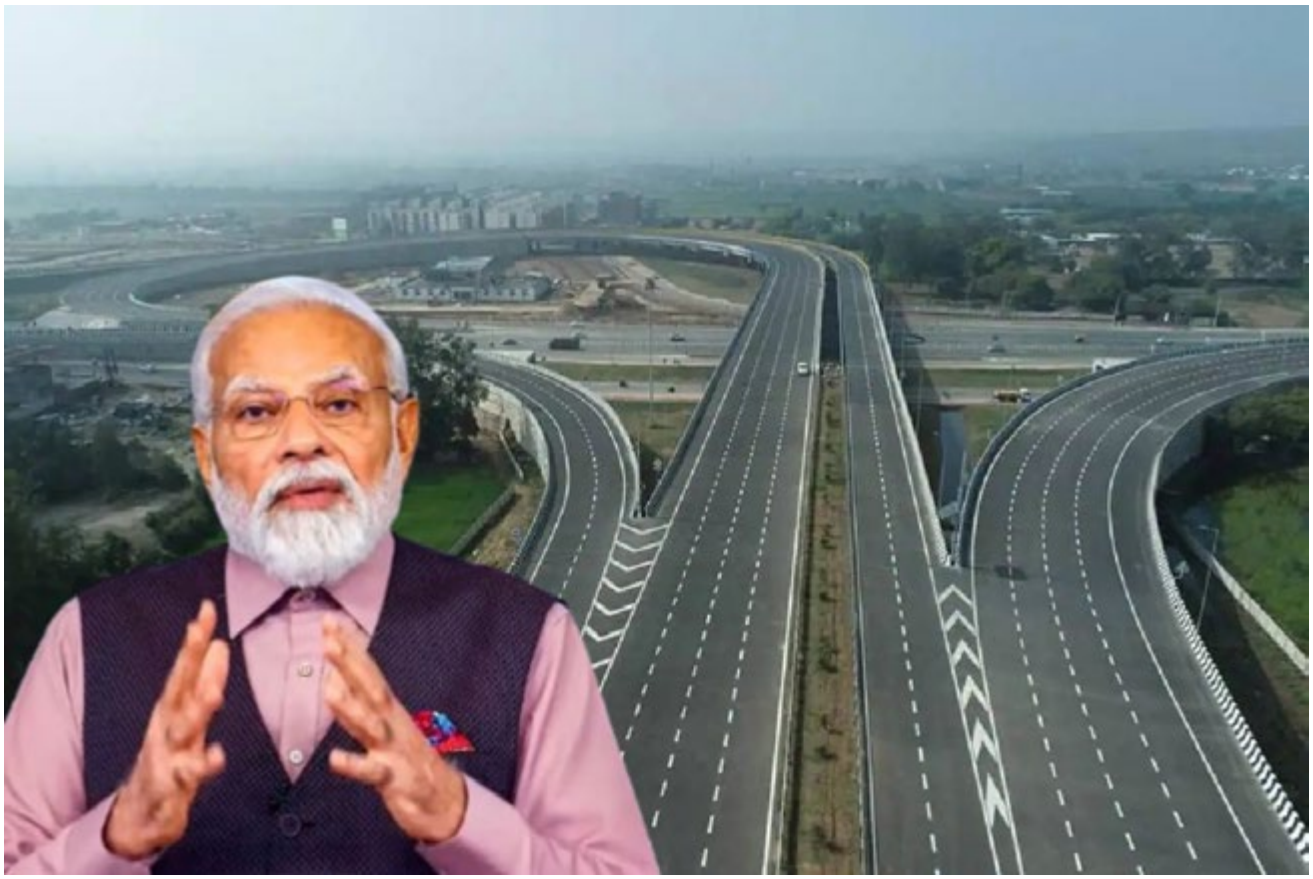

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार

पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति काफी उल्लेखनीय है, जो बजट आवंटन और निर्माण गति में वृद्धि को दर्शाती है। 2014 के बाद से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग बजट आवंटन में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे बुनियादी ढांचागत विकास में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में राजमार्ग निर्माण की गति 37 किमी/प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो देश में सबसे तेज राजमार्ग निर्माण का रिकॉर्ड है।

इसके अलावा 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का नेटवर्क 91,287 किलोमीटर था, जो वर्ष 2023 तक 60 प्रतिशत बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गया। चार-लेन एनएच की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई है। 2014 में यह 18,387 किलोमीटर था, जो नवंबर 2023 तक बढ़कर 46,179 किलोमीटर हो गया है। एनएच निर्माण की औसत गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2014 में बेसलाइन 12.1 किलोमीटर/प्रतिदिन से 143 प्रतिशत बढ़कर 28.3 किलोमीटर/प्रतिदिन हो गई है।

1,46,145 किलोमीटर तक फैले व्यापक नेटवर्क के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्रों को आपस में जोड़ने और पूरे देश में आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं 1,79,535 किमी तक फैले व्यापक राज्य राजमार्ग और 65,45,403 किमी तक फैले अन्य सड़क मार्ग भी विकास में अपना योगदान देते हैं।

पीएमजीएसवाई के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी में बदलाव

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 2014 से अब तक 3.74 लाख किमी लंबी सड़कों के निर्माण के साथ भारत ने ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचागत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप 99 प्रतिशत से

अधिक ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ा गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच और संपर्क स्थापित करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2013-14 में 3.81 लाख किमी की तुलना में अब तक 7.55 लाख किमी ग्रामीण सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं।

भारतमाला योजना के तहत व्यापक सड़क बुनियादी ढांचे का विकास

भारतमाला परियोजना को मुख्य रूप से देश भर में सामान और लोगों की आवाजाही की सुगमता को उपयुक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ शुरू किया गया था। इस परियोजना के प्रमुख घटकों में आर्थिक गलियारा विकास, इंटर-कॉरिडोर और फीडर मार्ग विकास, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़कें और एक्सप्रेस-वे शामिल हैं। भारतमाला परियोजना के तहत विकास के लिए 25 ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। इनमें से 20 पूरे हो चुके हैं या कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। भारतमाला परियोजना के चरण-I के तहत 34,800 किमी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना बनाई गई थी। दिसंबर-2023 तक लगभग 15,549 किमी का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 26,418 किमी (यानी 34,800 किमी का 76 प्रतिशत) सड़क बनाने का काम आवंटित किया जा चुका है।

भारत में रेल नेटवर्क का विकास

भारतीय रेलों का विकास आधुनिकीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह राष्ट्रीय प्रगति हेतु परिवहन आधारभूत संरचना को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से रेल यात्रा को सुगम बनाया गया

वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन ट्रेनों में उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, त्वरित गति और बेहतर यात्री सुविधाएं होने पर गर्व किया जाता है। ऑटोमैटिक प्लग डोर्स, रिक्लाइनिंग एर्गोनोमिक सीटें, एग्जिक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग सीट सहित बैठने की आरामदायक व्यवस्था, प्रत्येक सीट के लिए मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आदि से सुसज्जित इन ट्रेनों में आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलता है। 31 जनवरी 2024 तक भारतीय रेलवे में 100 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों की सेवाएं शुरू की गईं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वंदे भारत ट्रेनों की कुल सवारियां की दर 96.62 प्रतिशत रही।

इसके अलावा 12 मार्च, 2024 को प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि राज्यों को न सिर्फ ज्यादातर वंदे भारत ट्रेनें मिल गई हैं बल्कि वंदे भारत ट्रेनों ने शतक के आंकड़े को भी छू लिया है।

देश में रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार

भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। इस योजना के तहत पुनर्विकास के लिए चुने गए 1318 स्टेशनों के साथ महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।

भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण

भारतीय रेल परिवहन के पर्यावरण-अनुकूल, तेज और ऊर्जा-कुशल साधन प्रदान करने की दृष्टि से ब्रॉड गेज ट्रैक के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 तक कुल 61,508 रूट किलोमीटर (आरकेएम) के ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है, जो भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉड-गेज रूट (65,556 आरकेएम) का 93.83 प्रतिशत है। इससे पहले साल 2014 तक 21,801 किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया था।

भारत में मेट्रो रेल का विस्तार

भारत की मेट्रो रेल प्रणाली में विस्तार से शहरी आवागमन में क्रांतिकारी बदलाव आ गया है। 2014 में नेटवर्क की लंबाई 248 किमी थी, जो 2024 तक बढ़कर 905 किमी हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण वृद्धि शहरी आबादी को परिवहन में आसानी से सुविधा देने की मेट्रो रेल की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। इससे

प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ यात्री लाभान्वित हो रहे हैं। 2014 में केवल 5 शहरों तक ही मेट्रो की सुविधा थी। अब मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार देश भर के 20 शहरों तक हो गया है। 27 अतिरिक्त शहरों में 959 किमी लंबी लाइनें निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) कॉरिडोर पर चलने वाली भारत की पहली अत्याधुनिक नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और अपने परिवहन ढांचागत विकास को आधुनिक बनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भारत के विमानन क्षेत्र को बेहतर बनाना

उड़ान योजना की शुरुआत और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के संचालन के साथ भारत के विमानन परिदृश्य में बदलाव आया है। इस योजना से पूरे देश में कनेक्टिविटी और सुगमता से आवागमन में काफी योगदान मिला है।

नए मार्ग और हवाई अड्डे

विमानन क्षेत्र में उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के तहत संचालित 545 मार्गों के साथ महत्वपूर्ण विस्तार देखने को मिला है। इसका उद्देश्य देश के दूर-दराज और क्षेत्रीय इलाकों में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना है। देश में विकास के लिए हवाई मार्ग विस्तार के साथ-साथ 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की पहचान की गई है। इनमें से 12 का परिचालन शुरू हो चुका है, जो हवाई यात्रा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पिछले एक दशक से भारत का विमानन नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है। इस दौरान 158 परिचालित हवाई अड्डे और 84 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। 13 मार्च, 2024 तक 1.36 करोड़ से अधिक लोग हवाई यात्रा कर चुके हैं।

भारत के जलमार्गों का उपयोग

भारत के जलमार्गों में महत्वपूर्ण विकास देखा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के रूप में नामित किया गया है, जो अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी व व्यापार को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न क्षेत्रों में माल एवं यात्रियों के सुगम परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से विकास ने पकड़ी रफ्तार

सरकार ने बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें मौजूदा बंदरगाहों और टर्मिनलों का आधुनिकीकरण, बंदरगाह कनेक्टिविटी में वृद्धि, मछली पकड़ने के विशेष तट, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र आदि शामिल हैं। सागरमाला कार्यक्रम के तहत लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 839 परियोजनाओं का कार्यान्वयन होना है। इनमें से 1.22 लाख करोड़ रुपये की 241 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आंशिक वित्तपोषण के लिए सागरमाला योजना के तहत अब तक 4525 करोड़ रुपये की कुल 171 परियोजनाओं को सहयोग दिया गया है। 171 में से 55 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

रोपैक्स सेवाओं के साथ तटीय संपर्क मजबूत हुआ

सरकार ने रोपैक्स व यात्री नौका सेवाओं के माध्यम से यात्री एवं कार्गो परिवहन की सुविधा के लिए 57 स्थानों पर 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास किया है, जिनमें से 10 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 4 स्थानों पर

सेवाएं दी जा रही हैं। रोपैक्स सेवाओं के माध्यम से इस बेहतर सड़क संपर्क सुविधा ने वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर तटीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है, जिसने बदले में स्थानीय उद्योग एवं पर्यटन के विकास में योगदान दिया है।

रोपवे के माध्यम से संपर्क बढ़ाने पर जोर

रोपवे परिवहन का एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका बनकर सामने आया है। यह दुर्गम इलाकों में शुरू से लेकर आखिरी छोर तक संपर्क की महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है। इससे शहरी भीड़ को भी कम करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- पर्वतमाला

2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - 'पर्वतमाला' की घोषणा की। 132 किमी की कुल लंबाई वाली 32 परियोजनाओं को लेकर विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। सरकार इस कार्यक्रम को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रही है। भारत में बुनियादी ढांचागत विकास का निरंतर प्रयास विकास, संपर्क और आर्थिक समृद्धि को लेकर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

देश जैसे-जैसे अपने परिवहन नेटवर्क, शहरी सुविधाओं और डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करता है वैसे-वैसे यह स्थायी विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सभी लोगों के लिए बेहतर अवसरों की जमीन तैयार करता है।

ट्रांस्पोर्टेशन में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर...

PM मोदी की नेतृत्व में हो रहा काया-पलट, बदल दी तस्वीर

विनीत कुमार / न्यूज़ 18

भारत में जल्द ही बहुत अधिक मात्रा में माल ढुलाई के लिए हैवी हॉल मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें आधारभूत ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) का विकास एक महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक है. आधारभूत संरचना के विकास को लेकर देशभर में सड़कों का नेटवर्क, बंदरगाहों का विकास और रेल और हवाई नेटवर्क का विकास किया जा रहा है. तमाम राज्यों में जिन स्थानों तक पहुंचने में 24 घंटे का समय लगता था, वहां अब ठीक आधे यानी 12 घंटे में पहुंचना मुमकिन हो गया है.

ये एक्सप्रेसवे की शानदार और मल्टी लेन वाले सड़कों की वजह से हो सका है. इसी तरह वंदे भारत रेलगाड़ियों की वजह से अब दिल्ली से तमाम महत्वपूर्ण शहरों तक जाकर उसी दिन लौटने जैसी सुविधा भी मिल गई है. जिन जगहों में यात्रा के लिए लोगों को पूरी रात ट्रेन में गुजराना होता था वहां वे पांच से छह घंटे में पहुंच रहे हैं. इन सबसे महत्वपूर्ण काम डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर के निर्माण से हुआ है.

दरअसल, विकास को गति देने वाली यही जरूरी चीजें है. गति और समय की इस बचत लाभ यात्रियों को तो मिलता ही है इसका सबसे ज्यादा असर माल ढुलाई पर पड़ता है. माल अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से हो पाता है तो अर्थव्यवस्था को उसका बहुत व्यापक लाभ मिलता है, इसलिए देश में जल्द ही हैवी हॉल मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा.

अमेरिका और चीन में इस तरह की मालगाड़ी पहले से चल रही हैं और अब अपने देश में डेडीकेटेड फ्रेड कॉरिडोर (डीएफसी) में इसी तरह की मालगाड़ी चलाई जाएंगी, जिसे हैवी हॉल गुड्स ट्रेन कहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इस हैवी हाल गुड्स ट्रेन के तैयार कॉरिडोर का इसी सप्ताह उद्घाटन किया है. 1337 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न फ्रेड कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर पश्चिमी बंगाल के सोननगर तक जाता है. इसी के तहत 1506 किमी. लंबा वेस्टर्न कोरिडोर हरियाणा रेवाड़ी से महाराष्ट्र (अटेली से जवाहर लाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी) तक निर्माण चल रहा है. इस तरह से दोनों कॉरिडोर की लंबाई 2843 किमी है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कॉरिडोर का डिजाइन इस तरह किया गया है कि इसमें हैवी हॉल मालगाड़ियों का संचालन हो सके. इसकी क्षमता एक दिन में 120 हैवी हॉल मालगाड़ियां एक दिशा चलाने की है. एक हैवी हॉल मालगाड़ी में करीब 105 वैगन होते हैं और करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी इस गाड़ी में लगभग 13000 टन सामान जा सकेगा. इस प्रकार से एक मालगाड़ी करीब 1300 ट्रकों का सामान तेज गति से पहुंच सकेगा. इस तरह की मालगाड़ियों का संचालन अमेरिका और चीन में पहले से हो रहा है. अमेरिका के कोरोराडो में हैवी हॉल मालगाड़ियां से चल रही हैं और चीन के हुआंगहुआ और शुओझोउ में कोयला ढोने के लिए हैवी हॉल मालगाड़ियां का संचालन हो रहा है. वहीं आस्ट्रेलिया ने हैवी हॉल बैटरी वाले लोकोमोटिव का पिलबारा क्षेत्र में सफल परीक्षण किया है. जापान में सामान को जल्दी पहुंचाने के लिए हैवी हॉल मालगाड़ी के बजाए बुलेट ट्रेन इस्तेमाल होता है.

यात्री सुविधा का भी हो रहा है विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे का स्वदेशी और मजबूत नेटवर्क बनाने के साथ ही यात्री सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं. भारतीय रेलवे की स्थापना की लगभग पौने 200 साल हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारतीय रेलवे में सुविधा विश्व स्तरीय और कई मायनों में यह विश्व में सर्वोच्च हो जाए.

इसके लिए भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन क्रांतिकारी कदम उठाए हैं. इसके तहत पूरे देश में स्वदेशी विकसित वंदे भारत ट्रेन चलाए जा रहे हैं जिसमें विश्व स्तरीय यात्री सुविधा का ख्याल रखा गया है. इस ट्रेन को बनाते समय यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है. किसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रेलवे स्टेशनों को अत्यधिक तौर पर विकसित किया जा रहा है और इसी के तहत अमृत भारत स्टेशन की संकल्पना बनाई गई है. इस संकल्पना के तहत देश के विभिन्न स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों पर बनाया जा रहा है. इसके साथ ही साथ भारत में पहले रैपिड रेल नेटवर्क जिसमें नमो भारत ट्रेन चलाया जा रहा है यात्री सुविधा के लिए यह एक क्रांतिकारी पहल है. नमो भारत ट्रेन में यात्री सुविधा के साथ-साथ यात्रियों के समय की भी बचत और हाई स्पीड रैपिड रेल नेटवर्क बनाने की संकल्पना की गई है जिसके एक हिस्से को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्त रूप देते हुए राष्ट्र को समर्पित किया.

एक्सप्रेसवे से लेकर वंदे भारत की सौगात, दस वर्षों में नये भारत की तस्वीर

नवीन कुमार पाण्डेय

मोदी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के तेज विकास के जरिए एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला न्यू इंडिया बनाने की राह आसान की है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करके अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटने पर जोर दिया जा रहा है।

'स्केल भी और स्पीड भी।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासन का मूल मंत्र इसे ही बताते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि जो हो भव्य हो और लेट-लतीफी बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार के दो कार्यकाल में विभिन्न बुनियादी ढाचों के विकास पर गौर करेंगे तो पीएम के इस मंत्र का मतलब समझ आ जाएगा। सड़क हो या रेल या फिर हवाई अड्डे, 'पीएम गति शक्ति नैशनल मास्टर प्लान' के तहत हर क्षेत्र में बहुत तेज प्रगति हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की छवि ही मोदी सरकार के नगीने की हो गई है। उन्होंने हाइवेज और एक्सप्रेसवेज के निर्माण का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। स्थिति ये है कि विपक्ष के नेता भी गडकरी की खुले मन से प्रशंसा करते हैं। मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों के आकलन की सीरीज में आज बात इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। पिछले 10 सालों में देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव

देखने को मिले हैं। रेलवे और हाईवे को आधुनिक बनाने से लेकर जलमार्गों और हवाई परिवहन को नया स्वरूप देने तक, मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा जोर लगाया है।

हाइवेज और एक्सप्रेसवेज के बन रहे रिकॉर्ड

यह तो मोदी सरकार के विरोधी भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। बीते 10 वर्षों में देश के सड़क और राजमार्ग क्षेत्र ने अभूतपूर्व विकास और प्रगति देखी है। सरकार का दावा है कि पिछले एक दशक में 55 हजार किलोमीटर से ज्यादा हाईवे का निर्माण हुआ है। भारतमाला परियोजना जैसे प्रॉजेक्ट न केवल संपर्क को बेहतर बना रहे हैं बल्कि अछूते क्षेत्रों, आर्थिक केंद्रों और पर्यटन स्थलों की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना और नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी पहलों के माध्यम से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देकर सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर रही है।

भारतमाला परियोजना: 83,677 किमी नए राजमार्ग बनाने और 57,923 किमी मौजूदा राजमार्गों में सुधार करने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम। इससे राजमार्ग निर्माण की गति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 12 किमी की तुलना में प्रति दिन 37 किमी तक पहुंच गई है।

पीएम ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 5.3 लाख किमी से अधिक ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं, जिससे ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी लगभग 99% तक बढ़ गई है।

समर्पित माल ढुलाई गलियारे: इन उच्च गति, उच्च क्षमता वाली माल ढुलाई रेलवे का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स एफिसिएंसी में सुधार करना है। कई गलियारे निर्माणाधीन हैं, जिनमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिटेकेटेड फ्राइट कॉरिडोर शामिल हैं।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: दिल्ली को राजस्थान के लालसोट से जोड़ने वाले पहले 246 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन फरवरी में किया गया था। 2024 में पूरा होने पर पूरा एक्सप्रेसवे 1,386 किमी तक फैल जाएगा, जिससे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर केवल 12 घंटे रह जाएगा।

वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे: इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य वडोदरा और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सुगम परिवहन और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना है।

चारधाम कनेक्टिविटी हाइवे: उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना।

अन्य राजमार्ग विस्तार: 2025 तक सरकार की योजना मौजूदा 1,61,350 किमी नेटवर्क में 38,650 किमी राजमार्ग जोड़ने की है।

सुखद होती जा रही है रेल यात्रा

मोदी सरकार के बीते 10 वर्षों में रेलवे का कायाकल्प करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। बात रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन की हो या रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार की, नई ट्रेनें चलाने की हो या यात्री सुविधाओं में विस्तार की, रेलवे ने चौतरफा प्रगति की है। सरकार का दावा है कि 25 हजार किलोमीटर से अधिक नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं, जो कई विकसित देशों में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई से अधिक है। दावा यह भी है कि रेलवे विद्युतीकरण 94% तक बढ़ गया

है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हटा दिए गए हैं और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है। बायो-टॉयलेट्स, जीपीएस-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन रिजर्वेशन प्लैटफॉर्मों की शुरुआत ने यात्रियों के अनुभव को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है, जिससे ट्रेन यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक कुशल बनाया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहल और वंदे भारत एक्सप्रेस और नमो भारत जैसी स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेनों ने रेल यात्रा का अनुभव बेहतर कर दिया है। अब सोशल मीडिया के जरिए यात्री ट्रेनों में असुविधाओं की शिकायत करते हैं और उस पर तुरंत एक्शन भी होता है। हालांकि, यह भी सच है कि रेलवे के क्षेत्र में अभी बहुत काम करना बाकी है। खासकर, नई दिल्ली से कोलकाता के बीच ज्यादातर ट्रेनों में टिकट मिलना आज भी काफी मुश्किल है। इस लाइन पर ट्रैक जोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं दिखता है जिस पर अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है।

यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई, यात्री हेल्पलाइन (138), सुरक्षा हेल्पलाइन (182), कागजरहित अनारक्षित टिकट प्रणाली, ई-कैटरिंग, मोबाइल सिक्योरिटी ऐप और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा जैसी अनगितन सुविधाओं की शुरुआत हुई।

रेलवे अब अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में काम करेगा और खदानों, तटों आदि को आपस में जोड़ेगा। मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है।

वंदे भारत ट्रेनें: सरकार का लक्ष्य रेल कनेक्टिविटी और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए 400 वंदे भारत ट्रेनें (सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनें) बनाने का है।

अहमदाबाद मेट्रो रेल: शहरी परिवहन में सुधार के लिए अहमदाबाद, गुजरात में एक आधुनिक मेट्रो प्रणाली।

रेलवे अवसंरचना: सरकार ने लास्ट और फर्स्ट मील कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स की पहचान की है, विशेष रूप से बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए।

जलमार्गों का हो रहा विस्तार

अभी पिछले वर्ष ही हमारे देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ने अपनी यात्रा शुरू की थी। नाम है- गंगा विलास। मोदी सरकार में सागरमाला प्रॉजेक्ट जैसे प्रयास से समुद्री व्यापार और परिवहन को भी आसान बनाने पर जोर दिया गया है। ऐसे प्रयासों से जहां ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो रही है तो टिकाऊ विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। देश के अंदर के जलमार्गों की पूरी आर्थिक क्षमता का दोहन करने पर मोदी सरकार का खास फोकस है। गंगा विलास इसी का एक उदाहरण है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होने की गुंजाइश बनती है, बल्कि सड़क और रेल नेटवर्क पर बोझ भी कम होता है। 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

मोदी का मंत्र- उड़े देश का आम नागरिक

मोदी सरकार में एयरपोर्ट्स को लेकर भी बड़े पैमाने पर काम हुआ है। हवाई अड्डों और फ्लाइ रूट्स के विस्तार से आर्थिक विकास और यात्रा सुविधा में का विस्तार हुआ है। सरकार का दावा है कि 10 वर्ष में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। सरकार ने सस्ते हवाई सफर के लिए 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना लाई। इसके तहत छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं तो कई बंद पड़े एयरपोर्ट्स को फिर से ऐक्टिव किया जा रहा है। नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और प्रबंधन को गति मिल रही है। इससे उड्डयन क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है।

उड़ान योजना: इसका उद्देश्य कम सेवा वाले और बिना सेवा वाले हवाई अड्डों को जोड़ना है, जिससे हवाई यात्रा अधिक किफायती और सुलभ हो सके। इससे पिछले नौ वर्षों में 74 नए हवाई अड्डों का परिचालन शुरू हुआ है।

विस्तार और आधुनिकीकरण: बढ़ते यात्री यातायात को संभालने के लिए मौजूदा हवाई अड्डों को उन्नत किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल और रनवे का निर्माण किया जा रहा है।

जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: ग्रेटर नोएडा में स्थित इस हवाई अड्डे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: बढ़ते हवाई यातायात को संभालने के लिए मुंबई के पास एक प्रमुख हवाई अड्डा परियोजना।

दूसरा चेन्नई हवाई अड्डा: भीड़भाड़ कम करने और हवाई यात्रा क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई।

अब शहर-शहर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार

मोदी सरकार में देश के विभिन्न हिस्सों में मेट्रो का तेजी से विकास हुआ है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी परिवहन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। बीते 10 वर्षों में मेट्रो रेल सिस्टम वाले शहरों की संख्या चौगुनी हो गई है। 2014 में केवल पांच शहरों में मेट्रो थे, लेकिन अब 20 शहरों में मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इस तेजी से विकास ने न केवल प्रमुख शहरों में यातायात समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान किया है बल्कि यात्रियों को तेज, अधिक विश्वसनीय ट्रांसपोर्टेशन मोड मिल गया है। मेट्रो से यात्रा आसान तो होती ही है, तेज भी होती है। अभी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नै, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, पुणे, विशाखापत्तनम, गुवाहाटी, इंदौर, कोयंबटूर जैसे शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम ऑपरेशनल है।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ रहा भारत

मोदी सरकार ने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के अलावा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी खास जोर दिया है। यूपीआई के रूप में भारत का पेमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे आधुनिक और सबसे श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, सरकारी काम हो या पढ़ाई-लिखाई, हर क्षेत्र में डिजिटल सिस्टम को तेजी से बढ़ावा मिला है। मोदी सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में जाने की नौबत नहीं आए। इसी क्रम में अब अदालतों की सुनवाई का भी ऑनलाइन प्रसारण होने लगा है। कई मामलों में मुद्दई की अदालत में पेशी भी डिजिटल मोड में ही होने लगी है। सरकार का दावा है कि भारत भारतनेट और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए एक मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

- नवीन कुमार पाण्डेय सितंबर 2014 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं।

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee

Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

Phone: 011-69047014

@spmrfoundation